



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
 Part II—Section 3—Sub-section (ii)

लं० 429] नई विल्सी, शनिवार, सितम्बर 25, 1982/ग्राहित 3, 1904

No. 429] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 1982/ASHVINA 3, 1904

इस भाग में भिस पृष्ठ संख्या दो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Pagling is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उपरोक्त संशोधन

(औद्योगिक विकास विभाग)

आद्येष

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ), 25 ਸਿਤਾਮਹੁਨ, 19 2

क० आ० 688 (अ) / 18क० / आई० ई० 10 आ० ८२—भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (ओद्योगिक विकास विभाग) के अधिकार म० का० अ० 157 (ग्र) / 18क० / आई० ई० 10 आ० ८२/७९ नारीख 27 मार्च, 1979 द्वारा (जिसे इसके पश्चात् उन्न आदेश कहा गया है) कलकत्ता स्थित मैर्स लिली विस्कुट कम्पनी (प्राइवेट) नियुक्ते ओर लिली वारले मिल (प्राइवेट) लिमिटेड नामक ओद्योगिक उपकरणों का प्रबन्ध 27 मार्च, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था, और पश्चिमी बगाल सरकार के हण और बन्द उद्योग विभाग कलकत्ता के सचिव जिसे अब ओद्योगिक पूर्तनिमाण विभाग कलकत्ता के नाम से जाना जाना है को प्रधिकून नियतके के रूप में नियुक्त किया गया था, 763 GI/82.

और भारत मर्केट के उद्योग मन्त्रालय (शैद्योगिक विकास विभाग) के अधिकारी स.० का० आ० 178 (अ) /18 फ/प्राई० अ० ० प्रार० ८०/८२ तारीख २६ मार्च, १९८२ द्वारा उक्त आवेदन तारीख २७, मार्च, १९७९ की अवधि को २६ सितम्बर, १९८२ तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, बढ़ा दिया गया ।

और केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि लोकहिन में यह समीचीन है कि उक्त अधिकारी 27 मार्च, 1979 के उक्त भारत को 31 मार्च, 1983 तक की ओर अवधि के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उत्तरांग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के प्रत्यक्ष द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने द्वारा, यह निर्देश देती है कि तारीख 27 मार्च, 1979 का उक्त अधिनियम 31 नई, 1983 तक जिसके अन्तर्गत यह सारीख भी है को और प्रवधि के लिए प्रबाधी बना रहेगा।

[फ० स० २ (३)/८०-सी० य० एस०]

१०० प०० सर्वन, सम्पूर्ण सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th September, 1982

S.O. 688(E)/18A/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 157(E)/18A/IDRA/79, dated the 27th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Industrial Undertaking known as Messrs. Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs. Lily Bailey Mills (Private) Limited, Both located at Calcutta, had been taken over for a period of three years with effect from the 27th March, 1979 and the Secretary to the Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries, now known as Department of Industrial Reconstruction, Calcutta, was appointed as "Authorised Controller";

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 178(E)/18A/IDRA/82, dated the 26th March, 1982, the period of the said Order dated the 27th March, 1979, was extended upto and inclusive of the 26th September, 1982;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order dated the 27th March, 1979, should continue to have effect for a further period upto 31st May, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order dated the 27th March, 1979, shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st May, 1983.

[F. No. 2(3)/80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.